भारत को क्यातो घोषणा पर दस्तखत करना चाहिएः विशेषज्ञों की राय

कोलकाता, २२ अप्रैल (प्रेट्र)। पर्यावरणशास्त्रियों को मानना है कि भारत को क्यातो घोपणा पर दस्तखत कर देना चाहिए। इस पर ४० देश दस्तखत कर चुके हैं । इस धोपणा के लागू होने के बाद ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन पर रोक लग जाएगी।

गैर सरकारी संगठन कन्ज्यूमर यूनिटी ट्रस्ट सोसायटी कट्स न पहले पृथ्वी दिवस व्याख्यान का आयोजन यहां आज किया। इसमें तमाम विशेषज्ञो ने कहा कि भारत को क्यातो धोषणा पर दस्तखत कर देना चाहिए। पचपन देशों को दस्तखत कर देने पर यह लागू हो जायेगा। अब तक ४० देशों ने इस पर दस्तखत किए है। इनमें चेक गणराज्य और रोमानिया जैसे विकसित औद्योगिक देश भी हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक भारत के साथ दिक्कत यह है कि यह कितनी मात्रा में ग्रीनहाउस गैस वातावरण में छोड़ता है, इसका कोई तयशुदा नीति भी नहीं हैं। इसके बावजूद हम कुछ अंतर्राष्ट्रीय मानकों से बंधे हुए हैं। इसलिये हमें इस पर दस्तख्त कर देना चाहिए। इसमें मुख्य दिक्कत यह है कि सिर्फ चार वर्ष २००८—२०१२ के लिए ही उत्सर्जन मात्रा तय है । इसके बार कौन देश कितनी गैस वातावरण में छोड़ेगा, इस पर कोई रोक अब तक नहीं लगी। कई देशों को इस पर आपत्ति है ।

यादवपूर विश्वविद्यालय के सुजय बोस ने कहा कि भारत को अपने फॉसिल ईधन के खर्च में कटौती करनी चाहिए। कोयला, पेट्रोलियम वगैरह को फॉसिल ईंधन कहते हैं। भारत के पास भविष्य के संकट से बचने का एक मात्र उपाय इस तरह के ईंधन के खर्च में कटौती करना है। इससे ग्रीन हाउस गैस कम वातावरण में छोड़ी जायेगी और भविष्य में भारत को ईधन संकट से भी कम दिक्कत होगी।

मालुम हो, अमेरिका ने अब तक क्यातो घोपणा पर दस्तखत नहीं किया है। बुश प्रशासन इस मुद्दे पर साफ तौर पर कह रहा है कि यह उसके व्यवसायिक हित में नहीं हैं यूरोपीय संघ के साथ इस मुद्दे पर अमेरिका के तीखे मतभेद हैं।

बिट्रेन सहित पूरा यूरोपी संघ चाहता है कि इस पर अमेरिका दस्तखत कर दे। उसके दस्तखत किए बिना क्योतो घोषणा का कोई मतलब नहीं है, कयोकि सबसे अधिक ग्रीनहाउस गैस वातावरण में वही छोड़ता है।